आडवाणी का झूठ और राजनीति का सच

यह स्पष्ट हो चुका है कि भारत मे राजनीति का स्तर लगातार गिर रहा है। अच्छे लोग लगातार राजनीति से किनारे होते जा रहे है और पदलोलुप तिकडम बाज राजनीति मे घुसते जा रहे है। आम तौर पर माना जाता है कि राजनीति एक ब्यवसाय बन चुकी है। इससे बढकर राजनीति को गिरोह का रूप दिया जाने लगा है। पिछले दिनो भाजपा के प्रमुख नेता और कई बार प्रधानमंत्री के दावेदार रह चुके लाल कृष्ण आडवाणी ने नाटक किया। उस नाटक ने तो राजनीति को स्पष्ट रूप से बिल्कुल ही नंगा कर दिया।

आडवानी जी ने वीमारी का जो झुठ बेाला उस पर देश मे किसी को विश्वास नही हुआ। उसके बाद भी वे सफाई देते रहे कि वे वास्तव मे वीमार थे। उन्हे दस्त लग रहे थे । इतने बडे स्थापित व्यक्तित्व का ऐसा झूठ ऐतिहासिक ही माना जाएगा। जल्द ही स्पष्ट हो गया कि वे वीमार नही थे और उन्होने झूठ बोला । इससे भी आगे बढकर उनके पतन की तब और भी पराकाष्टा हो गयी जब उन्होने प्रधानमंत्री पद के प्रति अपनी दावेदारी पेश की और सारे भारत को यह संदेश दिया कि उनकी नाराजगी पर उनकी बीमारी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होने से दूर हो सकती है। प्रश्न उठता है कि प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी पार्टी की अमानत है या उनका अधिकार? स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री पद देश की जनता की अमानत है न कि किसी का अधिकार । उसी तरह प्रधानमंत्री पद की दावेदारी भी पार्टी की अमानत होती है। यह अलग बात है कि पार्टी के अन्दर अन्दर इस पद के लिये दावपेंच चलते रहते है । परन्तु कभी इतनी खुलकर मांगे नही होती जैसा कि आडवाणी जी ने किया। नरेन्द्र मोदी भी कई बार झूठ बोलने मे फस चुके है। आजमगढ की मुस्लिम महिलाओ का फोटो खिचवाकर उन्हे गुजरात का प्रकरण बताने मे अथवा ब्रिटेन के सांसदो को गुप्त रूप से प्रलोभन देकर भारत मे बुलाने की बाते जगजाहिर है। मोदी जी के रूठने की बात भी किसी से छिपी नही है। किन्तु आडवाणी जी के प्रकरण मे जिनता खुलकर झुठ बोला गया या प्रधानमंत्री पद का दावा पेश किया गया उसमे तो न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि हर राजनेता का सर झुका दिया। चाल चेहरा और चरित्र की बात कहने वाले इतना नीचे तक उतर जायेगे यह कभी सोचा भी नही गया था। पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओ को राष्टप्रेम, राष्टभक्ति, त्याग और बलिदान का उपदेश देते आडवाणी जी को भी कई बार सुना गया है। वही आडवाणी जी आज अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये सारा प्रवचन भूल गये। इससे तो अच्छा कांग्रेस पार्टी का चरित्र दिखा जिसके प्रधानमंत्री स्वयं राहुल गांधी के लिये पद छोडने की बात करते है अथवा सोनियां ने प्रधानमंत्री पद मिलता हुआ छोडकर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। एक ओर सोनिया मनमोहन सिंह का व्यवहार और दूसरी ओर नरेन्द्रमोदी आडवाणी की पद लोलुपता की आपस मे कैसे तुलना की जाय यह समझ मे नही आता। झूठ बोलने मे भी मनमोहन सिंह सोनियां गांधी से मोदी और आडवाणी कई गुना अधिक ना समझी करते देखे जाते है।

राजनीति मे कभी साधु सन्तों के समान नैतिकता की कल्पना नही की जा सकती। राजनीति मे कूटनीति तथा चालाकी होती ही है। किन्तु इसकी भी कोई सीमा तो अवश्य होती है। वैसे तो नेहरू काल से ही राजनीति मे नैतिकता का अभाव होता चला गया जो इन्दिरा गांधी के काल मे अपने चरम पर पहुंच गया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी राजनीति के स्तर मे कुछ सुधार किया तथा अटल जी के नेतृत्व मे भाजपा ने भी राजनीति मे नैतिकता को कुछ मजबूत किया। अटल जी के बाद भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नही सम्हाल सकी। भाजपा की आंतरिक राजनीति का स्तर भी गिरता गया और राष्ट्रीय राजनीति का भी । जिस तरह भाजपा ने मनमोहन सिंह के त्यागपत्र के नाम पर इतने महिने संसद ठप की वह बिल्कुल ही गलत था। मोदी जी ने भाजपा का नेतृत्व सम्हाल कर लगातार राजनीति मे छल प्रपंच को बढाया है। स्थिति यहां तक आई कि आडवाणी जी ने प्रधानमंत्री पद की इस तरह मांग करके राजनीति मे नैतिकता के स्तर को बिल्कुल ही नंगा कर दिया । अभी तो चुनावो को एक वर्ष बाकी हैं। देखिये आगे और क्या होता है।

1 श्री रविन्द्र अग्निहोत्री, इ मेल से

प्रश्न—ज्ञान तत्व दो सौ सत्तर मे आपने न्यायपालिका द्वारा सी बी आई को सरकारी पालतू तोता कहने को न्यायपालिका का अतिक्रमण करार दिया। मेरे विचार मे तो न्यायपालिका को इससे भी आगे बढकर कडे कदम उठाने चाहिये थे। जब विधायिका अपनी सीमाए भूल जावे तो क्या न्यायपालिका भी चुपचाप तमाशा देखती रहे? सीबी आई की रिपोर्ट को गुप्त रूप से देखना और फेर बदल करना पूरी तरह आपराधिक कार्य है। ऐसे लोगो को तो जेल मे बन्द होना चाहिये था। आपकी टिप्पणी चाहिये ।

उत्तर– मै आपसे सहमत हूँ कि विधायिका ने हमेशा ही अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया । न्यायपालिका ने विधायिका पर अंकुश न लगाया होता तो पता नहीं विधायिका क्या करती । आज भी कई सांसद संसद सर्वोच्च जैसा घमंड पाल कर रखते हैं। न्यायपालिका इसके लिये बधाई की पात्र है।

न्यायपालिका को विधायिका पर अंकुश तक ही स्वयं की सीमित रखना चाहिये था किन्तु न्यायपालिका इससे आगे बढकर सर्वोच्च बनने की दिशा मे बढने लगी। आज से साठ वर्ष पहले जब पण्डित नेहरू ने न्यायपालिका को कमजोर करना शुरू किया था तब भी हमने इसी तरह उसका स्वागत किया था किन्तु भविष्य मे वही विधायिका हमारे लिये भष्मासुर बनी और उस पर अंकुश के लिये हमे संविधान के अर्थों को तोडना मरोडना पडा।

यदि सी बी आई की स्वायत्तता पर विचार करे तो विधायिका हमेशा ही ऐसी संस्थाओ का दुरूपयोग करती है। सी बी आई को स्वतंत्र होना ही चाहिये। किन्तु क्या सी बी आई न्यायालय के नियंत्रण मे रहेगी? और नही तो उसका ढांचा क्या होगा। प्रश्न सी बी आई तक सीमित नही है। इस मामले मे अभी न्यायिक प्रक्रिया चल रही है । किन्तु विचारणीय प्रश्न यह भी है कि अभी अभी उत्तराखंड मे आई भयंकर बर्बादी मे हस्तक्षेप करते हुए न्यायालय ने भी अपनी मोनिटरिंग शुरू कर दी। आप विचार करिये कि उत्तराखंड विनाशलीला मे सुप्रीमकोर्ट किस अधिकार किस आवश्यकता से कूद पडा। सच बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं को सुप्रीम सिद्ध करने के चक्कर मे कूदा। यदि चुनाव का वर्ष नही होता तो इस मामले मे सरकार न्यायालय को अपनी सीमा बता सकती थी।

न्यायपालिका न्यायिक मामलो मे आदेश देने का पूरा अधिकार रखती है किन्तु न्यायालय को प्रशासनिक मामलों मे बहुत सतर्कता पूर्वक अति विशेष परिस्थिति मे ही कोई आदेश देना चाहिये। सर्वोच्च न्यायालय को तो विशेष सावधान रहना चाहिये क्योकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध कही अपील नही हो सकती। सर्वोच्च न्यायालय को प्राथमिक आदेश तो देना ही नही चाहिये क्योकि उसकी कहीं अपील नहीं है।

मेरे विचार मे चुनाव के बाद बनने वाली नई सरकार को यह कहना चाहिये कि सुप्रीम कोर्ट मे तीन माह से ज्यादा के मुकदमे प्राथमिक आधार पर सुने जायेगे। यह नही चल सकता कि न्यायालय का अपना काम तो पिछडता जावे और जनहित याचिकाएं प्राथमिक आधार पर सुनी जावे। यदि कोई जनहित चाचिका आती है तो उसे किसी उच्च न्यायालय को भेज दी जावे । सुप्रीम कोर्ट मे भी सुनवाई की समय सीमा तीन से छ माह निर्धारित कर दी जावे। विचारणीय यह भी है कि विधायिका का भ्रष्टाचार तो सबकी समीक्षा का विषय है किन्तु न्यायपालिका के भ्रष्टाचार की

समीक्षा कैसे होगी। न्यायपालिका ने तो स्वयं को लौह कवच से सुरक्षित कर रखा है। बेचारे प्रशान्त भूषण को सारे प्रमाण होते हुए भी कहीं सुनवाई न होना चिन्ता का विषय है। मेरा तो स्पष्ट मत है कि न्यायपालिका को अपनी सर्वोच्चता का भ्रम छोड देना चाहिये।

2 श्री राम दर्श त्रिपाठी, विल्थरा रोड बलिया,उत्तर प्रदेश

प्रश्न– ज्ञान तत्व मे आज की दिशा और दशा , राजनीतिक आर्थिक एंव सामाजिक विषयो पर भी अधिक से अधिक बाते पढने को मिलती है। परन्तु वर्तमान समय मे भारत वर्ष किस ओर जा रहा है। यह बात समझ मे नही आ रही है। महात्मा गांधी भारत को मूल रूप से भारत बनाना चाहते थे न कि अमेरिका, ब्रिटेन या अन्य परन्तु इनके विचारो के विपरीत यह देश अपनी सभी पुरानी मूल संसकृति विचार सोच और दर्शन को भुलाकर विदेशियो के पीछे दौड मे दौड रहा है।

1 उपरोक्त सम्बंध मे कौन दोषी है और कैसे हम अपनी मूल पर पुनः स्थापित हो सकते है।

2 देश मे राजनीतिक आधार पर ही इस समय देश का भविष्य बनने वाला है । क्या इस समय देश की राजनीति मे कोई सुधार हो सकता है और कैसे?

3 भ्रष्टाचार के इस युग मे स्वयं कोई ऐसी भुमिका है जिसके द्वारा आज पूंजीवाद का नाश हो सकता है।

पुनः क्या सन 1975 जैसे जे पी द्वारा चलाये गये आंदोलन की तरह कोई फिर आंदोलन सभी को मिलकर चलाया जाना सम्भव है जिससे पूर्ण जन तन्त्र भारत वर्ष मे आ सके और परिवार वाद जातिवाद सम्प्रदायवाद की समाप्ति हो।

उत्तर– 1 भारत आज जिस हालत तक पहुंचा है उसमे भौतिक उन्नति का श्रेय भी पंडित नेहरू की अर्थनीति को ही जाता है और नैतिक पतन का दोष भी उन्ही का है। नेहरू और अम्बेडकर ने मिलकर जो नीति बनाई वे उसके दोषी है।

2 संविधान संशोधन के अधिकार वर्तमान संसद से हटकर काल्पनिक लोक संसद को जाने से समाधान की शुरूआत संभव है।

3 भ्रष्टाचार का एक मात्र समाधान अधिकतम निजीकरण है और पूंजीवाद का समाधान अधिकतम समाजीकरण से संभव है।

4 अन्ना आंदोलन की विफलता के बाद नये चुनाव तक तो किसी आंदोलन की कल्पना व्यर्थ है । उसके बाद लोक संसद आंदोलन पर सोच सकते है।

3 अनिल अनवर , जोधपुर राजस्थान

प्रश्न– ज्ञानतत्व आरम्भ से आज तक नित्य मिलता रहा है जिसमें आपके विचारों तथा अन्य विद्वान विचारकों के लेख व शंका – समाधान पढ़ कर मुझे अच्छा लगता है। परन्तु कई बार मैं यह भी सोचने पर विवश होता हूॅ कि विचारों को कार्यरूप में परिणत कर पाना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आजकल कितना कठिन है। भारत की राजनीतिक – सामाजिक दशा में परिवर्तन लाने हेतु तथा गरीब की आर्थिक उन्नति करने के लिए आप के विचार सर्वथा मौलिक होते हुए भी व्यावहारिक रूप में न अधिकांश जनता तक पहुॅच पाये हैं, न ही स्वार्थ – बुद्धि से मतदान करने वाले या मतदान ही न करने वाले लोग इन विचारों की गहराई को आत्मसात कर संविधान परिवर्तन या व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रेरित हो पाये हैं। भारत की राजनीति जो दिशा ले रही है वह आप से छिपी भी नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि वैचारिकों के विचार आज केवल वाग्विलास में बदल गए हैं जहॉ दो–तीन विद्वान भी विचार–विमर्श कर एकमत नहीं हो पाते हैं, जबकि धूर्त राजनेता स्वार्थ के वशीभूत अद्भुत एकता में बॅध कर राजनीति दल बना कर मनमानी करने में सफल हो जाते हैं तथा आम जनता भी उन्हें ही स्वार्थवश वोट देती है जो पतित होते हैं। ऐसे में आपका अभियान बहुत साहस भरा व प्रशंसनीय होने पर भी असफल सिद्ध हो रहा है।

तथापि मैं आपका प्रशंसक अवश्य हूॅ भले ही निजी परिस्थितियों वश सक्रिय सहायक बन सकने की पात्रता न पहले रखता था, न अब रखता हूॅ। ज्ञान तत्व के प्रचार प्रसार के लिए आर्थिक रूप से भी कोई बड़ा योगदान कर पाने की क्षमता मुझ में नहीं विकसित हो पाई है क्योंकि मेरी सारी उपभोग से शेष बची आय (आय को स्त्रोत केवल सरकारी पेंशन) 'मरू गुलशन' पत्रिका के प्रकाशन/वितरण में लग जाती है। फिर भी मुझे लगता है कि ज्ञान तत्व एक महत्वपूर्ण वैचारिक पत्रिका है तथा इसका अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार अभियान को सबल बनाने हेतु उपयोगी सिद्ध होगा। समस्या यह है कि जो लोग लिखने–पढ़ने में रूचि रखने वाले बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, उनको वैचारिक क्रान्ति से कुछ लेना देना ही नहीं है क्योंकि उन सभी के राजनीतिक विचार पूर्वाग्रह ग्रस्त हैं। आप एक कम्युनिस्ट या आर0 एस0 एस0 वाले, कांग्रेसी, सर्वोदयी या इस्लामपरस्त व्यक्ति के विचारों को परिवर्तित नहीं कर सकते क्योंकि ये सब तर्क की बात सुनना ही नहीं चाहते। ऐसे में गरीब के श्रम का मूल्य कैसे बढ़े या कृत्रिम ऊर्जा किस प्रकार से बहुत महॅगी करके साइकिल या बीड़ी सस्ती की जाए, इन बातों पर कोई राजनीतिक दल या नेता विचार ही नहीं करना चाहता। हमारे आपके सोचने व सहमत होने से कोई विशेष फर्क ही नहीं पड़ता। रामानुजगंज एक छोटा स्थान था जहॉ आपका प्रयोग आंशिक रूप से या पूर्णतः सफल हो गया परन्तु देशव्यापी जन जागरण कैसे सम्भव होगा?

अन्ना हजारे व अरविन्द केजरीवाल के मार्ग अलग हो जाने के बाद तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी सही नेतृत्व कहीं नजर नहीं आता। मनमोहन सिंह ढलान पर हैं। राहुल गॉधी अपरिक्व तथा नरेन्द्र मोदी तानाशाही प्रवृत्ति के हैं। आप स्वयं अब सन्यास के मार्ग पर चल पड़े हैं ऐसे में लोक स्वराज्य की परिकल्पना साकार होती हुई कम से कम मुझे तो निकट भविष्य में कहीं नजर नहीं आती। अहिंसक तरीके से संविधान परिवर्तन चुनाव जीते बिना सम्भव नहीं परन्तु अन्ना हजारे समेत ईमानदार लोग चुनावी राजनीति में ही कदम रखने को तैयार नहीं हैं। चुनाव जीतने का प्रश्न ही नहीं है।

मैं निराशावान हूॅ कि ऐसे में ज्ञान तत्व पत्रिका किस प्रकार लोक स्वराज्य का अग्रदूत बनेगी। मैं आपको कुछ नए पाठकों के लिए ज्ञान तत्व भेजने का आग्रह तो कर रहा हूॅ। पते संलग्न हैं किन्तु मैं स्वयं भी आश्वस्त नहीं हूॅ कि इनमें से कितने लोक स्वराज्य अभियान में रूचि लेकर आपके साथ जुड़ पायेंगे। मेरा ई मेल नहीं है क्योंकि मैं कम्प्यूटर शिक्षित ही नहीं हूॅ। फोन नम्बर 0291–2671917 तथा मोबाइल

उत्तर– विचारक के लिये यह आसान नही होता कि वह अपने जीवन काल मे विचारो को कार्य रूप मे परिणीत कर सके। विचारक के विचार समाज ही कार्य रूप मे परिणीत करता है। कार्य रूप मे परिणीत करने के लिये जिस संगठन कला की आवश्यकता है वह विचारक मे आम तौर पर नही होती। मै भी इस कमी का शिकार हूॅ । मुझे उम्मीद थी कि सर्वोदय लोक स्वराज्य को बढाने मे आगे आयेगा और बंग साहब तथा सिद्धराज जी सरीखे लोग इस कार्य को समझे भी किन्तु सर्वोदय का ही एक समूह इस दिशा मे चलने के बिल्कुल विरूद्ध हो गया इसलिये लोक स्वराज्य का कार्य प्रारंभ नही हो पाया । मेरे प्रयत्न असफल रहे।

मै यह मानता हूँ कि मै देश भर के अनेको शहीद हुए है। वे जिन्हे यह पता था कि उनकी शहादत कोई तात्कालिक परिणाम नही देने वाली है फिर भी उन्होने स्वयं को बलिदान किया और ऐसे शहीदो से प्रेरणा पाकर ही आज हम स्वतंत्र हो पाये है। मुझे यह पता होते हुए भी कि मेरे जीवन काल मे कोई परिवर्तन संभव नही दिखता किन्तु लोक स्वराज की मशाल जीवित रखना भी कोई साधारण कार्य नही है। संभव है कि यह मशाल भविष्य मे किसी विस्फोट मे परिणीत हो जाय।

यह सही है कि दो तीन विद्वान भी बैठ कर एक मत नही हो पाते है जबकि राजनेता एकमत हो जाते है । उसका कारण है कि राजनेताओ मे स्वार्थ एक संयुक्त ऐजेडा होता है। विचारको के बीच ऐसा कोई संयुक्त ऐजेन्डा नही होता जो उन्हे किसी मुद्दे पर एक जुट कर सके। ऐसा आम तौर पर होता ही है। विचारो से निकले निष्कर्ष के प्रचार प्रसार के लिये संगठन की आवश्यकता होती है जो हमारी टीम के पास नही है। जब कि समाज मे अनेक संगठन ऐसे है जो लोक स्वराज्य की धारणा का सैद्धान्तिक रूप से विरोध करते है । संघ परिवार इस्लाम तथा साम्यवाद तो इस विचार के विरोधी है ही किन्तु सभी राजनैतिक दल भी इस विचार के पूरी तरह विरोधी है। एक तरफ उसकी ताकत को तौल कर अपनी तुलना करना बहुत कठिन है किन्तु पूर्व काल मे भी अनेक ऐसे अवसर आये है जब विचारको को ऐसी ही तुलना मे स्वयं को ढकेलने की हिम्मत करनी पडी है। मैने भी वैसी हिम्मत की है । गांधी के बाद जय प्रकाश ने लोक स्वराज्य की मशाल को जिंदा रखने का प्रयास किया और उसके बाद अन्ना हजारे ने भी आंशिक कोशिश की। उनकी असफलता से सबक लेते हुए भी मै उस मसाल को जलाये रखता हूँ। इस उम्मीद के साथ कि भविष्य मे यह मशाल काम आयेगी । मै भी मानता हूँ कि संविधान संशोधन के लिये संसद मे जाना एक मार्ग है किन्तु एक और मार्ग भी ह ै कि सशक्त जनमत के समक्ष राजनेता झुक जावे जैसा कि अन्ना जी के समीप दिखा था । दोनो ही कार्यो मे एक बात आवश्यक है कि प्रबल जनमत खडा हो । जब तक प्रबल जनमत खडा नही होगा तब तक कोई निर्णय करना कठिन है। मैने यदि सन्यास के मार्ग पर चलने की राह पकडी है तो उसका उद्देश्य मुक्ति की कामना नही है। उसका उद्देश्य तो है कि सब काम छोडकर ऐसे प्रबल जनमत जागरण मे अपनी सारी शक्ति लगाई जाए। आप हमेशा हमारे मिशन के शुभ चिन्तक रहे है । भविष्य मे भी कभी कभी पत्र लिखकर हमे मार्ग दर्शन देते रहे। झक झोरते रहे कि कही हम अपने प्रयत्नो मे शिथिल न हो जावे । अभी हम तीन कार्यो पर अपना सारा ध्यान केन्द्रित कर रहे है पहला है 130 गांवो मे नई समाज रचना की शुरूआत करना। दुंसरा समाज मे फैलायी गयी असत्य धारणाओ को चुनौती देना तथा तीसरा है लोक संसद के मुद्दे पर देश भर मे राजनैतिक जन जागरण करना। जब तक संसद के एकाधिकार मे कोई कटौती नही होगी तब तक कोई बात आगे नही बढेगी । लोक संसद के एकाधिकार मे पांच प्रतिशत कटौती करने का प्रस्ताव है। इन तीनो कार्यो पर हम सारी शक्ति लगा रहे है। सफलता असफलता का आकलन किये बिना आप सबके सहयोग की अपेक्षा है।

4 आई एस अग्रवाल मुंगेली बिलासपुर छत्तीसगढ

प्रश्न—आपने लिखा कि पेट्रोल का दाम बढाकर सौ रूपया कर देना चाहिये । इससे अन्य पेट्रोलियम पदार्थो के दाम भी बढेगे और दाम बढने के परिणाम स्वरूप इनकी खपत घटेगी तथा आयात खर्च मे बचत होगी । यह तो आपका एक पक्ष हुआ किन्तु इसका दूसरा पक्ष भी है कि इससे आवागमन मंहगा होगा और आवागमन मंहगा होने के कारण सभी उपभोक्ता वस्तुए मंहगी हो जायगी। आपने संभवत इस पक्ष पर विचार नही किया। आप अपनी बात को और स्पष्ट करे।

उत्तर— मेरा पूरा प्रस्ताव इस प्रकार है कि कृत्रिम उर्जा के सभी प्रदार्थ डीजल, बिजली, पेट्रोल मटटी तेल गैस कोयला का मूल्य ढाई गुना कर दिया जावे। इससे प्राप्त धन से वर्तमान मे लग रहे कृषि उत्पाद वन उत्पाद ग्रामीण उत्पाद तथा ग्रामीण उपभोग की सभी वस्तुओ को टैक्स फ्री कर दे। साथ ही देश की आधी आबादी को दो हजार रूपया प्रति व्यक्ति प्रतिमाह की उर्जा सब्सीडी दे दे। इस तरह भारत मे प्रट्रोल का मूल्य एक सौ पचहत्तर रूपये करीब हो जायगा। इसी के अनुसार बिजली डीजल आदि भी बढ जायेगे। आवागमन मंहगा हो जायगा। किन्तु आवागमन मंहगा होने के बाद भी आम उपभोक्ता वस्तुएं मंहगी नही होगी। क्योकि उनपर लगने वाला सरकारी टैक्स खतम हो जायगा। वर्तमान मे सरसो तेल पर करीब आठ रूपया प्रति लीटर का टैक्स लगता है । आवागमन मंहगा होने के बाद भी आठ रूपये से कम ही प्रभाव पडेगा। सभी वस्तुओ पर इसी तरह अप्रत्यक्ष कर लगता है।

आवागमन महंगा होने से ग्रामीण उद्योग मजबूत होंगे । शहरी आबादी घटेगी और गांवो की ओर पलायन होगा। श्रम की मांग बढेगी और मूल्य भी बढेगा। सारा मशीनी उत्पादन मंहगा हो जायगा। श्रम मूल्य वृद्धि से कृषि उत्पादन भी मंहगा होगा। देश मे कृत्रिम उर्जा सरप्लस होने से तथा श्रमिक उर्जा पशु उर्जा सहायक हाने से सब चीजो का उत्पादन बढेगा और हम ज्यादा से ज्यादा निर्यात कर सकेंगे। यदि उत्पादन लागत बढने से निर्यात मे दिक्कत होगी तो निर्यात मे सब्सीडी देकर उसे युक्तिसंगत करना होगा।

यह एक आमूलचूल आर्थिक परिवर्तन का कदम होगा। उच्च वर्ग की आय घटेगी खर्च बढेगा मध्यम वर्ग को न कोई लाभ होगा न हानि। निम्नवर्ग की आय बढेगी और खर्च घटेगा। निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के बीच बढती जा रही आर्थिक असमानता अपने आप कम हो जायगी। मुझे तो लगता है कि श्रम का दैनिक मूल्य लगभग दो गुना हो जायगा। सम्पन्न वर्ग बहुत चिल्लायेगा। मध्यम वर्ग को लाभ हानि नही है किन्तु वह भी सम्पन्न वर्ग के साथ साथ विरोध करेगा किन्तु यह सभी आर्थिक समस्याओ का एक मात्र समाधान है।

इस योजना से कुछ अन्य लाभ भी होंगे। सौर उर्जा गोबर गैस जट्रोफा आदि का उत्पादन बिना सब्सीडी बढ जायगा। पर्यावरण प्रदूषण अपने आप कम हो जायगा। खाडी देशो से तेल आयात एकदम कम हो जायगा। क्योकि भारत के ही विभिन्न श्रोत बहुत बिजली बना देगे । उत्पादन बढने से निर्यात भी बढ सकता है। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे वालो के प्रति परिवार दस हजार रूपया मासिक उर्जा सब्सीडी मिलने से आर्थिक विषमता का हल्ला ही नही रहेगा। मुझे तो ऐसा नही लगता कि इस योजना से कोई हानि होगी किन्तु यदि कोई हानि होगी भी तो वह लाभ की तुलना मे नगण्य होगी। हमारा देश थोडा सा प्रकृति की ओर लौटेगा। टैक्टर के साथ साथ बैल भी खेतो मे दिखेंगे। कृषि उत्पादन पर से टैक्स हटेगा तथा उसका मूल्य भी लगभग दो गुना हो जायगा। आप देखियेगा कि किस प्रकार कृषि उत्पादन तेज गति से बढता है । यह योजना भ्रष्टाचार भी घटा देगी। क्योकि टैक्स का श्रोत एक होगा और सब्सीडी भी एक होगी। सस्ता राशन सस्ता तेल की जरूरत ही नही रहेगी।

5 श्री कुलदीप सक्सेना सिविल लाइन्स कानपुर उत्तर प्रदेश

सुझाव— कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू है। दोनो ही अमेरीका और बहुराष्ट्रीय कम्पनी के हितो को संरक्षित करने का कार्य कर रहे है। अमेरिका डार्विन थ्योरी जो ताकतवर है वही राज करेगा की नीति का पालन कर रहा है। गांधी के कमजोर को भी जीने का अधिकार की भावना भंवर जाल मे फंस कर काफी गहराई तक जा पहुंची है। जरूरत है कि इन दोनो से इतर अन्य ताकतो जैसे गांधीवादी समाजवादी वामपंथी

तथ जल जंगल जमीन से जुडे सक्रिय समाजिक संगठनो को एक जुट कर तीसरी ताकत खडी की जाए जो देश के आमजन को मकडजाल से निजात दिला सके और बेलगाम अफसर शाही को जनोन्मुख कर सके।

उत्तर– साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच तुलना करे तो दोनो ही आदर्श नही है किन्तु पूंजीवाद की अपेक्षा साम्यवाद अधिक खतरनाक है। जिस इकाइ के पास सेना पुलिस न्याय सरीखे शक्तिशाली हथियार हो उसे ही सारे वित्तीय अधिकार देना न्यायसंगत नहीं। बाजारवाद की बुराइयां स्पष्ट है। इनसे हटकर समाज समाज व्यवस्था की दिशा मे जा सकता है। किन्तु राष्टीयकरण के बाद तो कही दूसरी ओर देखना भी कठिन है। हमारे राष्टीयकृत उधोगो का भ्रष्टाचार जग जाहिर है। इनके घाटे की भरपाई अन्य टैक्स लगाकर होती रही है। स्कूलो की हालत देख लीजिये। प्राइवेट स्कूलो मे खर्च की तुलना सरकारी स्कूल से करे तो आखे फटी की फटी रह जायगी। उपर से पढाई का स्तर देखिये । सरकार को अधिकतम निजीकरण कर देना चाहिये। सरकारी घाटे पूरे करने के लिये ग्रामीण उत्पादनो पर कर लगाकर पूर्ति होती है । बहुत ही कष्ट की बात है। चाहे सभी स्कूल बन्द हो जावे किन्तु ग्रामीण उत्पादन उपभोग की सभी वस्तुए टैक्स फ्री होने चाहिये । शिक्षा के लिये श्रम पर कर कैसे न्याय संगत है।

जब तक आपका आवागमन मंहगा नही होगा तब तक बडे उद्योगो को निरूत्साहित नहीं कर सकते । श्रम का शोषण चाहे भारतीय बडे उद्योग करें या बहु राष्ट्रीय कम्पनियां किन्तु श्रम को इससे फर्क नही पडता। अमेरिका तथा बहु राष्ट्रीय कम्पनियों का विरोध यदि ग्रामीण अर्थ ब्यवस्था की मजबूती के लिये हो तो उसका स्वागत है किन्तु यदि यह विरोध सरकारीकरण के लिये हो तो विरोध घातक है। कांग्रेस और भाजपा जिस अर्थनीति की ओर बढ रहे है उसका विकल्प दिये बिना यदि विरोध होता है तो कही न कही फिर से सरकारीकरण का अप्रत्यक्ष समर्थन हो जायेगा जो ठीक नहीं।

आपने कांग्रेस भाजपा से अलग एक मोर्चा बनाने की बात कही। स्पष्ट है कि गांधी लोहिया जय प्रकाश चौखम्बा राज के पक्षधर थे। गांवो को अपनी सीमा मे प्रशासनिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता देनी चाहिये तब गांधी लोहिया जय प्रकाश मजबूत होंगे। साम्यवाद और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नीतिगत रूप से इसके विरूद्ध है। वास्तव मे गांधीवाद के लिये दो ही विचारधाराएं अछूत है। इन दोनो से अलग ही कुछ संभव है। परिवार तथा गांव लगातार टूट रहे है। उन्हे लगातार सरकार पर निर्भर किया जा रहा हैं । एक मोर्चा गांधी लोहिया जय प्रकाश के मानने वालों का तो बन सकता है। किन्तु संघ और साम्यवाद कभी अकेन्द्रीयकरण को स्वीकार नही करेंगे। उनके साथ तो कोई मोर्चा केवल अवसरवादित होगी। जिस तरह गांधीवादियों मे वाम पंथियो की घुसपैठ हुई और उन्होने गांधीवाद को ही पथ भ्रमित कर दिया वह चिन्ताजनक है। मेरे विचार मे यही गांधीवाद थोडा भी वामपंथ से मुक्त होकर आगे आवे तो कुछ कांग्रेसी कुछ भाजपाई भी जुड सकते है। समाजवादी शक्तियां गांधीवाद के चौखम्बा राज को लेकर शुरू आत करे। संभव है कि कोई मार्ग निकल सके।

6 श्री रामलाल नागर, सहावर कासगंज

प्रश्न–1 उत्तर प्रदेश सरकार ने केवल वोट की खातिर सिर्फ अल्प संख्यको की वच्चियों को आर्थिक सहायता देकर राजस्व मे अन्य समुदायों की बच्चयो की अनदेखी करते हुए भारतीय संविधान, जो समानता का सूचक है, की गरिमा को बेइज्जत किया है।

2 उत्तर प्रदेश सरकार के मुसलिम विधायक सिर्फ मुसलमानो की ही प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप मे सहायता करते है। इंसाफ को ताक मे रख दिया हे।

3 राशन वितरण प्रणाली को बदलने की जरूरत है क्योकि एफ सी आई के सभी अधिकारी सरकारी राशन की दुकान कही जाने वाली दुकान के दुकानदार से मासिक कमीशन लेते है, ऐसी जानकारी मिली है। जिसकी वजह से राशन डीलर साल मे चार बार ही राशन बाटते है वो भी सरकारी रेट सें 2/3 रूपये किलो व लीटर बढा कर पैसे वसूलते है। प्रदेश की गरीब जनता को खाद्य सहायता नही मिल पाती है शिकायत करने पर र्कमचारी डीलर को बुलाकर रिश्वत लेकर कोई कार्यवाही नही करते है।

4 ग्राम पंचायतों के प्रधान और खंड विकाश कर्मी मिलकर सरकार से विकास कार्यो के लिये मिलने वाली धन राशि को बंदरवाट कर लेते है। सदस्यो को कोई नही पूछता है। फर्जी हस्ताक्षर कर लेते है।

5 आप से आशा है कि उपरोक्त के विषय मे अपने स्तर से सुधारात्मक कार्य करे ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके।

उत्तर– वर्तमान समय मे भ्रष्टाचार कोई बुराई न होकर बुराई का परिणाम है। भ्रष्टाचार के कारण अब्यवस्था नही बढ रही है बल्कि अब्यवस्था के कारण भ्रष्टाचार बढ रहा है। व्यवस्था करने वालो की नीयत खराब है । खराब नीयत के लोग सत्ता मे जाकर अनावश्यक कानून बनावे जिनसे दिन दूना रात चौगुना भ्रष्टाचार बढे और हम उस भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयत्न करे। यह मुझे ठीक नहीं लगता । हजारो वर्षो से पण्डित जी और सेठ जी गन्दा करते थे तो हरिजन जी साफ करते थे । अब ऐसा नही होना चाहिये कि नेता लोग गन्दगी फैलावे और हम साफ करे।

अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का विचार ही घातक है तथा समाज को तोडने के उद्देश्य से नेहरू अम्बेडकर एण्ड कम्पनी की देन है। राशन वितरण प्रणाली का उद्देश्य भी अपने चमचो को राशन वितरण मे घुसाकर भ्रष्टाचार करने के लिये बनी है। ग्राम पंचायतो के प्रधान भी उसी भ्रष्ट राजनैतिक व्यवस्था की एक कडी है। मेरा मत है कि हम राज्य के समाज के आन्तरिक मामलो मे न्यूनतम हस्तक्षेप की मांग करें। भारत के प्रत्येक नागरिक को एक प्राथमिक इकाई माना जाय । परिवार गांव जिला को संवैधानिक मान्यता मिले तथा उनके अधिकार तथा शक्तियां परिभाषित हो। लोकतंत्र को लोक नियत्रित तंत्र मे सुधार कर बदला जाए। ऐसा मेरा विचार है। फिर भी यदि आप वर्तमान व्यवस्था मे सुधार के कुछ कार्य कर रहे है तो मेरा आपको समर्थन रहेगा। किन्तु मै अपनी शक्ति इधर से हटाकर भ्रष्टाचार रोकने की दिशा मे नही लगा सकता।

7 श्री हरिशचंद्र जैन अधिवक्ता मेरठ कैंट उत्तर प्रदेश फोन न0–09798033594

प्रश्न– आप जितना बड़ा काम कर रहे हैं, लगभग पूरा समय आप देश की अच्छाई के लिये लगा रहे हैं। मेरा आपके द्वारा किये जा रहे प्रयत्नों के लिए साधुवाद।स्वराज्य या स्वशासन पर आप अधिक जोर डाल रहे हैं लेकिन मैं स्वराज्य को ठीक प्रकार, साधारण शब्दों में या प्रयोगात्मक भाव में भली प्रकार समझने में असमर्थ सा पाता हूॅ। जहॉ तक आज की भारत उसकी अच्छाईयों व बुराइयों को भली भांति समझ रहा हूॅ और उससे सम्बन्धित जो आप 'ज्ञान तत्व' में लिखते हैं। उससे सहमत भी हूॅ और शायद सभी सहमत हैं।

शासन की दशा से हम भली भांति परिचित हैं। समस्त प्रबुद्ध वर्ग इससे त्रस्त भी हैं एवं ईमानदार शासक वर्ग भी इन सब से परिचित है ऐसा लगता है। लेकिन अल्प वर्ग में हैं जो चाहते हुए भी शायद नहीं कर पा रहे हैं। कुछ बाते फिलवक्त मेरी जुबान पर है जो मैं आपको अपनी टूटी फुटी भाषा में लिख रहा हूॅ।

– भ्रष्टाचार चरम पर है । उसको जड़ से समाप्त होना असम्भव सा लग रहा है। आप जैसे कितने लोग होगें जो भ्रष्टाचार समूल नष्ट करने के हामी है।

हमारा ढांचा गल सड गया है इसका नवीनीकरण परम आवश्यक है। अन्ना जी भी ऐसा ही कुछ कहते है व्यवस्था परिवर्तन भारत वर्ष के अनुशासन का पाठ प्रत्येक नागरिक के लिये आवश्यक हो फिर शायद इतने कानून एक्ट, रूल्स, गर्वमेन्ट, आडर्स नोटिफिकेशन एक्ट की आवश्यकता ही न रहे। भ्रष्टाचारी एंव उनके पालतू लोग आज सत्ता मे बहुतायत मे है और सत्ता मे रहने के लिये उनका संरक्षण शायद आवश्यक हो गया है। सत्ता आई कानून का संरक्षण जिसको मिल गया समझो वो अनुशासन भूल गया। किसी भी वर्ग को सरकारी संरक्षण प्राप्त नही होना चाहिये। इतिहास हमारे सामने है।

सरकारी कर्मचारी की रिष्पोंशब्लिटी व एकाउन्टलीटी तय हो और वो घर घर तक पहुचाई जाये।

प्रबुद्धो मे प्रबुद्ध व्यक्ति सरकार अपने कार्यो के लिये लेती है। जबकि कम्पनीयां उनके निम्नवर्ग के प्रबुद्धो अपने कार्यो के लिये लेती है। लेकिन सरकारी कर्मचारी असफल और निजि कम्पनियां सफलता से अपने कार्यो को अन्जाम देती है। सरकारी कर्मचारी इतनी तनखा और छूट के बावजूद भ्रट हो जाता है एंव निजी कर्मचारी अधिकतर भ्रष्ट नही होतां कारणन समझाने की आवश्यकता नही। सरकार को अपनी इच्छा शक्ति को संचित करन ही होगा । अन्यथा जनता त्राहि त्राहि ही करती रहेंगी। अधिकाधिक लोगो को नही मालूम किसी सरकारी विभाग की कमी या गलती या सर्वाधित कार्य के लिये किस से सम्पर्क करे। सरकार द्वारा जारी किये गये टेलीफोन या तो बन्द पडे है या सुनकर अनदेखी कर रहे है । लाखो करोड की सरकारी छूट जो गरीबो के लिये थी। सरकारी अमीर डकार गये । मुझे मालुम है वटन दबाते ही तबदीली नही आने वाली परन्तु कदम तो बढाये जो जनता तारीफ करे। दिन प्रतिदिन समस्याएं बढती ही जा रही है। क्या हर समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये जाम धरना भूख हडताल और कुछ लोगो की जान जाना आवश्यक है?

व्यवस्था परिवर्तन आवश्यक है। आज की जरूरत है।

बहुत कुछ जहन मे हैं। दुखी हूॅ । मै ही नही मेरे जैसे बहुत लोग और आप जैसे तो न जाने कितने कितने लोग दुखी है। आप बहुत मेहनत मनन कर रहे है । आपको मेरे साधुवाद । प्रभु आपको अपने प्रयासो सफलता प्रदान करे।

उत्तर–आपने जो लिखा है वह सच्चाई हैं।यह समस्या तो है ही यदि विस्तार पूर्वक समस्याओं की चर्चा करें तो दस बीस पृष्ठ भी पूरे हो सकते हैं।किन्तु चर्चा का मुख्य आधार होना चाहिए समाधान न कि सिर्फ समस्या।

मेरा मानना हैकि भारत में भौतिक उन्नति बहुत हुई है और हो भी रही है।दूसरी ओर चरित्रपतन भी बहुत हुआ है और लगाातर बढ़ रहा है राजनैतिक व्यावस्था समाज में भौतिक उन्नति की और भूख पैदा कर रही है चरित्र पतन को रोकने की चर्चा भौतिक उन्नति की चर्चा में प्रायः डूब जाती है । आवश्यकता यह है कि भौतिक उन्नति की बाधाओं के सामाधान की चर्चाओं से किनारा करके नैतिक अवनति की रोकथाम पर चर्चा आगे बढ़े।

अन्ना जी का मार्ग अन्य लोगो की अपेक्षा ज्यादा ठीक है यह स्पष्ट है । अरविन्द केजरीवाल की लाइन बिलकुल अस्पष्ट है।मनमोहन सिंह,नीतिश कुमार कोशिश तक सीमित है। अन्य अनेक राजनेता सत्ता की बंदर बॉट से आगे बिल्कुल भी नहीं दिखते ।मुझे तो कभी–कभी रामदेव जी के विषय में भी महसूस होता है कि वे भी कुछ–कुछ सत्ता संघर्ष की दिशा मे फिसल रहे है।

सीधी–सीधी बात है कि राज्य, समाज में वर्ग निर्माण वर्ग विद्वेष वर्ग संघर्ष को हथियार बनाकर स्वंय बिल्लीयों के बीच बन्दर की भूमिका में रहना चाहता है। राज्य स्वंय को संचालक तथा समाज को संचालित सिद्ध कर रहा है ।हम चाहते है कि सामाज और राज्य के बीच जो वर्तमान बिल्ली बंदर की भूमिका है वह या तो बिल्कुल पलट जावे अथवा दोनों की असमानता घटे। सत्ता संघर्ष में लगे लोग इस समाज और राज्य के बीच बढ़ रही असमानता की चर्चा का मार्ग बदलकर भौतिक या आर्थिक विषमता की ओर मोड़ देते है। हम चाहते हैं कि समाज के वर्तमान धर्म,जाति,भाषा,क्षेत्रीयता,उम्र,लिंग,गरीब अमीर,उत्पादक उपभोक्ता जैसे विषय आधारित संगठन कमजोर होकर परिवार गॉव ,जिला ,प्रदेश देश और विश्व जैसे संगठन मजबूत हों।समाज तोड़क संगठन भी पूरी ताकत से सक्रिय हैं।किन्तु अब हम नगण्य होते हुए भी उन्हें कड़ी टक्कर देने की ओर बढ़ रहेहैं । हमें स्वयं समझना होगा कि समाज सर्वोत्तम हैं और राज्य समाज की अनेक सहायक इकाइयों में एक । मैं कहता हूॅ कि राज्य का सामाजिक समस्याओं के समाधान में पैर डालना गलत हैं । लोग पूछते हैं कि यदि समाज अपनी समस्या न सुलझा सके तो क्या राज्य भी चुप बैठा रहे? ऐसा लगता है कि यह गंभीर प्रश्न है जबकि यह प्रश्न ही गलत है । प्रश्न यह है कि यदि राज्य किसी समस्या का समाधान न करे या न कर सके तब ऐसी समस्याओ का समाधान कौन करेगा? निश्चित रूप से समाज को ही समाज को ही आगे आना होगा। तो क्यो न राज्य सुरक्षा और न्याय तक सीमित रहकर सामाजिक समस्याओं के समाधान से बाहर कर ले।बड़ी संख्या में भारतीय विद्धान राज्य को समाज से भी उपर निर्णायक इकाई के रूप में देखते है। उनकी यह सोच बदलनी चाहिए ।हम इस संबंध में प्रयत्नशील हैं।

8. श्री रिषभ जी जागरूक ,जयपुर ,राजस्थान

प्रश्न –मैने आपको तीन पत्र लिखे किन्तु आपने एक का भी उत्तर नहीं दिया । लापरवाही है। ज्ञान तत्व पढ़ने से मुझे लगा कि आप प्रधानमंत्री पद के लिए नरेन्द्र मोदी के पक्ष में है । मेरे विचार में भी देश को ऐसा ही दबंग आदमी चाहिए ।इस संबंध में मैं मोदी का पक्षधर हूॅ।

आप देश भर की नदियों को जोड़कर एक ग्रिड बनाने पर अपनी शक्ति लगाइये ।अटल जी के कार्यकाल में यह बात चली थी किन्तु रूक गई।अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी झंडी दे दी है। यह मुहिम आगे बढ़ सकती है। आप यह भी बताइये कि ज्ञान तत्व की वर्तमान में कितनी प्रतियॉ देश भर में जाती है। मैं लगातार आपके साथ हूॅ क्योंकि आपका शुभ चिन्तक हूॅ । कभी –कभी सुझाव देता हूॅ। मैं चाहता हूॅ कि आप उत्तर दें।

उत्तर– यह सही है कि मै आपके पत्रो के उत्तर नही दे सका। पत्रो मे कोई व्यक्तिगत बात न होने से व्यक्तिगत उत्तर आवश्यक नही था। यह मेरी लापरवाही नही थी। प्रधानमंत्री पद के लिये मै नरेन्द्र मोदी को पहला विकल्प न मानकर अन्तिम विकल्प मानता हूॅ। क्योकि नरेन्द्र मोदी से देश की समस्याए सुलझने की संभावना है और समाज की गुलामी का खतरा है। अंग्रेजो के समय देश गुलाम था समाज स्वतंत्र था। स्वतंत्र सत्ता के बाद देश स्वतंत्र हो गया और समाज गुलाम । मजबूत प्रधानमंत्री से सामाजिक गुलामी बढेगी। मनमोहन सिंह सबसे अच्छे प्रधान मंत्री है क्योकि वे

दबंग नही है। नीतिश कुमार मे भी अच्छी योग्यता है। नरेन्द्र मोदी तो मजबूरी है । यदि लालू ममता मायावती जय ललिता सरीखे लोग दिखे तो नरेन्द्र मोदी का पक्ष प्रबल होगा । मुझे दिखता है कि मेरी पसंद के मनमोहन सिंह तीसरा कार्यकाल भी ग्रहण करेंगे।

आपने देश की नदियों का एक ग्रिड बनाने की बात की । मै उससे सहमत हूँ । आप पहल करिये । मेरा समर्थन रहेगा। मै पहल नही कर सकता ।क्योकि मै लोक संसद के मुद्दे पर देश भर के विद्वानो का एक ग्रिड बनाना चाहता हूँ। मै लोक संसद को व्यवस्था परिवर्तन के साथ जोडकर देखता हूँ जबकि नदियों का मुद्दा व्यवस्था मे सुधार का।

दौलत राम पटेल मंदसौर मध्य प्रदेश

सादर अभिवादन । आपका पत्र ज्ञान तत्व निरंतर प्राप्त होता आ रहा है। स्वयं पढने समझने और योग्य कटिंग निकालने के बाद मंदसौर नगर मे स्थित प0 दीनदयाल उपाध्याय बहुउद्देश्यय वृद्ध सेवा केन्द्र याने केअर सेन्टर पर पहुचाया जाता है। ताकि नगर के अन्य वरिष्ठजन भी लाभ उठा सके।

आपका जबावी पोस्टकार्ड नियत समय पर प्राप्त हुआ। पर मै समय पर प्रति उत्तर नही भेज सका। कारण व्यक्तिगत पारिवारिक संगठनात्मक वार्षिक बैठको तथा पत्र व्यवहार आदि भेजने पर अधिक ध्यान देना रहा। अपेक्षानुसार नये पाठको के नाम यथा शीघ्र भेंजूगा।

आपके 1 से 15 मार्च 2013 के अंक मे प्रकाशित हुए आपके लेख शाहरूख खान की पीडा कितनी यथार्थ कितनी भ्रम को अलग से टाइप कराकर एक पत्रक मुस्लिम बन्धुओ मे वितरण हेतु तैयार कराया गया है और इसकी प्रतियां दो मुस्लिम संगठनो के भारतीय विचार के कार्यकर्ताओ के सौजन्य से छपवाकर बंटवाने हेतु कहा गया। पर वे शायद हिम्मत नही जुटा पाये। अतः यह सपना अधूरा ही है। इससे स्पष्ट है कि मुस्लिम बंन्धुओ की मानसिकता हम नही बदल पा रहे है और इसका स्पष्ट कारण भारत मे जय चंदो तथा मीर जाफरो के वंशज याने विचार के जो है वे इनकी मानसिकता राष्ट्रवादी बनने नही देना चाहते । यह विचारणीय है । क्योकि जयचंदो के इतिहास के दुष्परिणामो को हमारा देश सैकडो वर्षो से भुगतता जो आ रहा है। इस बीच अपने घर पर रखा वर्षो पुराना शासकीय सेवा व संगठनो मे कार्य करते रहते रहने का जो रेकार्ड इकठ्ठा हो रहा है उसे समेटने या सहेजने और अनावश्यक को निपटाने के समय भाई श्री गोविन्दाचार्य जी का पत्र भी निकला। इसमे भी आपका उल्लेख रहा है। अतः इसकी प्रति आपके अवलोकनार्थ संलग्न की जा रही है। आप वैचारिक परिवर्तन लाने मे लगे हुए है। श्री गोविन्दाचार्य जी कितने सफल हो पाये यह शायद आपकी समझ मे होगा। हम समझ नही पा रहे है । साथीगण भी असमंजस की स्थिति मे है। खैर आपका मिशन सफल हो । इसकी कामना के साथ पत्र देने मे विलम्ब के लिये झमा प्रार्थी हूँ। अब कमजोरी महसूस होती है। अतः आना जाना कम होता जा रहा है।

उत्तर– शाहरूख खान को समझाना संभव है यदि नीयत साफ हो । इस्लाम का उत्तर हिन्दू राष्ट न है न हो सकता है। हिन्दू राष्ट्र शब्द जिस कट्टर हिन्दुत्व की ओर इशारा करता है वह तो इस्लाम को भी और अधिक कटृर बनने की ओर प्रेरित करता है। धार्मिक कट्टरवाद मे हिन्दू मुसलमान का भेद संभव नही । इस संबंध मे अपने विचार लिखे। गोविन्द जी लगातार सक्रिय है यद्यपि कोई परिणाम नही दिख रहा। फिर भी वे प्रयत्नशील है। यही पर्याप्त है।